

बैंकों का नजीकरण

प्रिलमिस के लिये:

भारत में बैंकिंग और संबंधित कानून, भारतीय रज़िर्व बैंक, 'एसेट रकिंस्ट्रक्शन कंपनी' (बैंड बैंक),

मेन्स के लिये:

बैंकों का नजीकरण, इसका महत्त्व और संबंधित मुद्दे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण

प्रमुख बटु

हाल ही में सरकार ने बैंकिंग कानून (संशोधन) अधियक 2021 के कुछ प्रमुख पहलुओं पर फरि से वचिर करने का नरिणय लरिया है, जसिका उद्देश्य संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का नजीकरण करना है।

- पछिले सत्र में सरकार ने इस संबंध में एक अधियक पारति कथिया थल, जो सामान्य बीमल वयवसलय (रलषट्रीयकरण) संशोधन अधियक, 2021 के माध्यम से रलज्य के स्वामतित्व वलली सामान्य बीमल कंपनरियों के नजीकरण की अनुमतल देतल है।

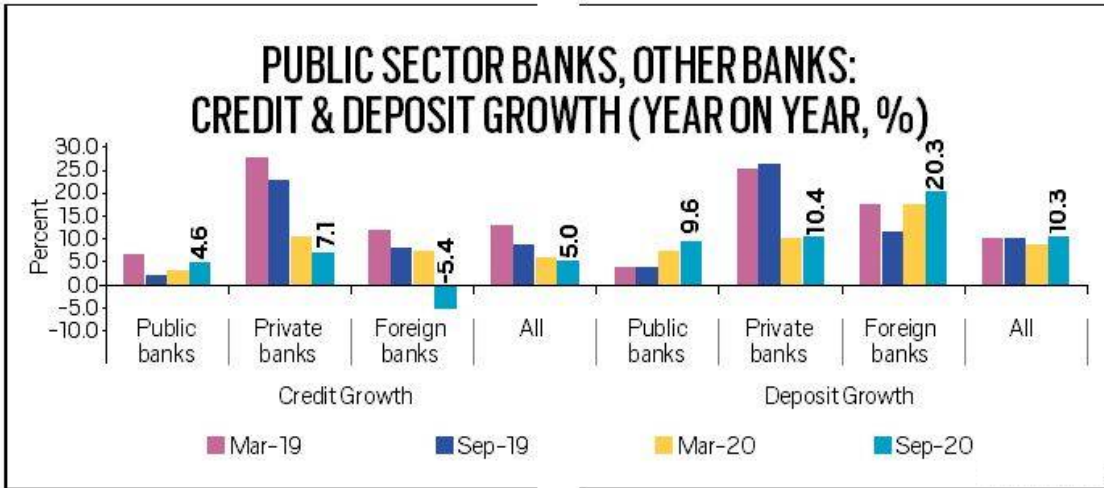
बैंकिंग कानून (संशोधन अधियक) 2021

- केंद्रीय बजट 2021-22 में वतित मंतरी द्वारा बतलए गए वनरिवश लक्ष्यों को पूरल करने के लथि दो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के नजीकरण हेतु अधियक कल उद्देश्य वर्ष 1970 और वर्ष 1980 के बैंकिंग कंपनरियों के अधग्रहण और हसतलंतरण कलनूनों तथल बैंकिंग वनरियमन अधनरियम, 1949 में संशोधन करना है।
 - इनहीं कलनूनों के माध्यम से बैंकों कल रलषट्रीयकरण कथिया गथल, ऐसे में नजीकरण कल मलरुग प्रशसत करने हेतु इन कलनूनों के प्रलसंगक प्रलवधलनों को बदलनल आवश्यक है।
- इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में न्यूनतम सरकलरी हसिसेदलरी 51% से कम होकर 26% हो जलएगी।

प्रमुख बटु

- परचिय
 - नजीकरण
 - सरकलर से नजी क्षेत्र में स्वामतित्व, संपततथल वयवसलय के हसतलंतरण को नजीकरण कलहल जलतल है। इसके तहत सरकलर इकलई वयवसलय की स्वामी नहीं रह जलती है।
 - नजीकरण को कंपनी में अधकल दकषतल और नषिपकषतल ललने की दृषटलसे अधकल महत्त्वपूर्ण मलनल जलतल है।
 - भलरत वर्ष 1991 के ऐतहलसकल सुधलर के बलद नजीकरण की ओर आगे बढल थल, जसलसे 'नई आरथकल नीतल' वल एलपीजी नीतल के रूप में भी जलनल जलतल है।
 - रलषट्रीयकरण
 - रलषट्रीयकरण नजी तौर पर नथलंतरतल कंपनरियों, उदयुगों वल संपततथल को सरकलर के नथलंतरण में रखने की प्रकुरथल है।
 - ऐसल अकसुर वकलसशील देशों में होता है और संपततथल को नथलंतरतल करने वल वदलशी स्वामतित्व वलले उदयुगों पर अपने प्रभुत्व कल दलवल करने की देश की इच्छल को प्रतबलबलतल करतल है।
- पृषठभूमल
 - केंदुर सरकलर ने वर्ष 1969 में देश के 14 सबसे बडे नजी बैंकों कल रलषट्रीयकरण करने कल नरिणय लरिया थल, इस नरिणय कल उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को तत्कललीन सरकलर के समलजवलदी दृषटकलण के सलथ संरेखतल करना थल।
 - भलरतीय स्टेट बैंक (SBI) कल वर्ष 1955 में और देश के बीमल क्षेत्र कल वर्ष 1956 में रलषट्रीयकरण कर दथल गथल थल।

- पछिले 20 वर्षों में वभिन्न सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नजीकरण के वरिद्ध रही हैं। वर्ष 2015 में सरकार ने नजीकरण का सुझाव प्रस्तुत किया था, हालांकि **भारतीय रज़िर्व बैंक** (RBI) के तत्कालीन गवर्नर इस विचार के पक्ष में नहीं थे।
- बैंकों द्वारा पूरण स्वामित्व वाली एसेट रकिंस्ट्रक्शन कंपनी (बैड बैंक) की स्थापना के साथ नजीकरण के वर्तमान प्रयास वित्तीय क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिये बाज़ार आधारित समाधान खोजने के दृष्टिकोण का नेतृत्व करते हैं।



■ नजीकरण के कारण

○ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति:

- केंद्र सरकार द्वारा वर्षों तक पूंजीगत निवेश और शासन व्यवस्था में सुधार किये जाने के बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया है।
- इनमें से कई सार्वजनिक बैंकों की तनावग्रस्त संपत्तियाँ नजी बैंकों की तुलना में काफी अधिक हैं और साथ ही उनकी लाभप्रदता, बाज़ार पूंजीकरण और लाभांश भुगतान रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है।

○ दीर्घकालिक परियोजना का हिससा

- दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नजीकरण से एक दीर्घकालिक परियोजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कुछ चुनदा सार्वजनिक बैंकों की परकिलपना की गई है।
 - सरकार की प्रारंभिक योजना चार बैंकों के नजीकरण की थी। पहले दो बैंकों के सफल नजीकरण के बाद सरकार आने वाले वित्तीय वर्षों में अन्य दो या तीन बैंकों के वनिवेश पर जोर दे सकती है।
- यह नरिणय सरकार, जो क बैंकों में सबसे बड़ी हसिसेदार है, को बैंकों को वर्ष-प्रतविरष वित्तीय सहायता प्रदान करने के दायतव से मुक्त करेगा।
 - बीते कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप अब सरकार के पास केवल 12 सार्वजनिक बैंक मौजूद हैं, जिनकी संख्या पूर्व में कुल 28 थी।

○ बैंकों को मज़बूती प्रदान करना

- सरकार बड़े बैंकों को और अधिक मज़बूत बनाने का प्रयास कर रही है तथा नजीकरण के माध्यम से बैंकों की संख्या में भी कमी की जा रही है।

○ अलग-अलग समितियों की सफ़ारिशें

- कई समितियों ने सार्वजनिक बैंकों में सरकारी हसिसेदारी को 51% तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है:
 - **नरसमिहन समिति** ने हसिसेदारी को 33% तक सीमित करने की बात की थी।
 - **पी.जे. नायक समिति** ने हसिसेदारी को 50% से कम करने का सुझाव दिया था।
- हाल ही में RBI के एक कार्यकारी समूह ने बैंकिंग क्षेत्र में बड़े व्यावसायिक घरानों के प्रवेश का सुझाव दिया है।

○ बड़े बैंकों का नरिमाण:

- नजीकरण का एक उद्देश्य बड़े बैंक बनाना भी है। जब तक नजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मौजूदा बड़े नजी बैंकों में वलिय नहीं किया जाता है, तब तक वे उच्च जोखमि लेने की क्षमता और उधार देने की क्षमता वकिसति नहीं कर सकते हैं।
- ऐसे में नजीकरण एक बहुआयामी कार्य है, जिसमें कई चुनौतियों से निपटने और नए विचारों की खोज करने के लिये सभी दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है, लेकिन यह सभी हतिधारकों को लाभान्वित करने के लिये एक अधिक सतत् और मज़बूत बैंकिंग प्रणाली वकिसति करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

■ मुद्दे:

○ क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा:

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नजीकरण बैंकों को नजी कंपनियों को बेचने के समान है, जिनमें से कई ने **PSBs** के ऋण को वापस नहीं किया है जिससे क्रोनी पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है।

○ नौकरी के नुकसान:

- नजीकरण से बेरोज़गारी, शाखा बंद होना और वित्तीय बहषिकरण जैसी गतविधियाँ प्रभावित होंगी।
- नजीकरण से **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनय पछिड़ा वर्ग (ओबीसी)** के लिये रोज़गार के अवसरों को कम होंगे क्योंकि नजी क्षेत्र कमज़ोर वर्गों के लिये आरक्षण नीतियों का पालन नहीं करता है।

- **कमज़ोर वर्गों का वित्तीय बहिष्करण:**
 - नज़ि क़्षेत्र के बैंक अधिकि संपन्न वर्गों और महानगरीय/शहरी क़्षेत्रों की आबादी पर अधिकि ध्यान केंद्रति करते हैं, जसिसे समाज के कमज़ोर वर्गों, वशिष रूप से ग्रामीण क़्षेत्रों में वित्तीय बहिष्कार होता है।
 - सार्वजनकि क़्षेत्र के बैंक बैंकगि को ग्रामीण क़्षेत्रों तक पहुँच और वित्तीय समावेशन को सुनशिचति करते है। इन्होंने आशंका जताई है कि अगर सार्वजनकि क़्षेत्र के बैंकों का नज़िकरण कयिा गया तो इन लाभों पर वपिरीत प्रभाव पड़ सकता है।
- **बेलआउट ऑपरेशन:**
 - बैंक यूनयिनों ने नज़िकरण प्रक्रयिा को कॉरपोरेट डफिऑल्टरों के लयि "बेलआउट ऑपरेशन" का नाम दयिा है।
 - बड़े पैमाने पर फँसे ऋण के लयि नज़िक क़्षेत्र ज़मिमेदार है और उन्हें इस अपराध की सज़ा मलिनी चाहयि। लेकनि सरकार बैंकों को नज़िक क़्षेत्र के हवाले कर उन्हें पुरस्कृत कर रही है।
- **शासन के मुद्दे:**
 - **इंडस्ट्रयिल क्रेडिटि एंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडयिा (ICICI) बैंक** के एमडी और सीईओ को कथति तौर पर संदगिध ऋण देने के आरोप में बरखास्त कर दयिा गया था।
 - **यस बैंक** के सीईओ को आरबीआई ने एकसटेशन नहीं दयिा और अब वभिनिन एजेंसयिों की जाँच का सामना करना पड़ता है।
 - **लकष्मी वलिास बैंक को परघिालन संबंधी समस्ययाओं** का सामना करना पड़ा और हाल ही में इसे डीबीएस बैंक ऑफ सगिापुर के साथ वलिय कर दयिा गया।

<

बैंकगि वनियिमन अधनियिम, 1949

- यह भारत में बैंकगि फर्मों को नयित्तरति करता है। इसे बैंकगि कंपनी अधनियिम 1949 के रूप में पारति कयिा गया था।
- यह अधनियिम भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) को अधिकार देता है:
 - वाणज्यकि बैंकों को लाइसेंस जारी करना, शेयरधारकों की हसिसेदारी और वोटगि अधिकारों को वनियिमति करना, बोर्डों और प्रबंधन की नयिकृत्तिका पर्यवेकषण करना, बैंकों के संचालन को नयित्तरति करना, ऑडिट के लयि नरिदेश देना, नयित्तरण स्थगन, वलिय और परसिमापन, जन कल्याण के हति में बैंकों को नरिदेश जारी करना, बैंकगि नीति और यद आवश्यक हो तो बैंकों पर जुरमाना लगाना आदि।
- सरकार ने वर्ष 2020 में बैंकगि वनियिमन अधनियिम, 1949 में संशोधन के लयि एक अध्यादेश पारति कयिा, जसिसे सभी सहकारिताएँ रज़िर्व बैंक की नगिरानी में आ गई, ताकि जमाकर्त्ताओं के हतियों की ठीक से रकषा की जा सके।

आगे की राह:

- बैंक ऋणों पर वलिफुल डफिऑल्ट (Wilful Defaults) को "आपराधकि कृत्तय" मानने के लयि एक उपयुक्त वैधानकि ढाँचा लाने की तत्काल और अनविर्य आवश्यकता है।
- उधार देने और **गैर-नषिपादति** आसतयिों के प्रभावी समाधान के लयि वविकपूर्ण मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है।
- PSBs के शासन और प्रबंधन में सुधार करना होगा। ऐसा करने का एक उपाय **पी.जे. नायक समति** द्वारा सुझाया गया था, जहाँ सरकार और शीर्ष सार्वजनकि क़्षेत्र नयिकृत्तयिों (जसिके संबंध में सारे कार्य बैंक बोर्ड बयूरो को करने थे लेकनि वह अकषम रहा) के बीच दूरी रखने की अनुशंसा की गई थी।
- अंधाधुंध नज़िकरण के बजाय PSBs को **जीवन बीमा नगिम (LIC)** जैसे नगिम में रूपांतरति कयिा जा सकता है। सरकारी स्वामतिव बनाए रखते हुए इनका नगिमीकरण PSBs को अधिकि स्वायत्तता प्रदान करेगा।

स्रोत:द हनिदू